

यह अध्याय वित्त लेखे की लेखापरीक्षा पर आधारित प्रमुख राजकोषीय संग्रह में परिवर्तन का विश्लेषण एवं 31 मार्च 2020 को बिहार सरकार की वित्तीय स्थिति का आकलन करता है।

1.1 राज्य की रूपरेखा

बिहार एक भूमि से घिरा राज्य है, जो पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में झारखंड और उत्तर में नेपाल के साथ एक लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा से घिरा है। यह भौगोलिक आकार (94,163 वर्ग किमी) के मामले में भारत का बारहवाँ सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या (12,23 करोड़) की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। बिहार राज्य में 38 जिले हैं।

बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि प्रधान है और राज्य के पास कोई महत्वपूर्ण खनिज संपदा नहीं है। जैसा कि **परिशिष्ट 1.1** में दर्शाया गया है, जनसंख्या का घनत्व 881 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. (वर्ष 2001) से बढ़ कर (वर्ष 2011) में 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. हो गया है। अखिल भारतीय औसत की तुलना में बिहार में गरीबी का स्तर अधिक है। हालाँकि, राज्य ने 2011-12 से 2019-20 की अवधि के दौरान आर्थिक विकास में मामूली वृद्धि दिखाई है क्योंकि इसके सकल राज्य घरेलू उत्पाद की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सी.ए.जी.आर.) सामान्य श्रेणी के राज्यों के 11.98 प्रतिशत की तुलना में 12.00 प्रतिशत रही है। राज्य की प्रति व्यक्ति जी.एस.डी.पी. 2019-20 के अंत में ₹ 50,735 था, जबकि झारखंड, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का प्रति व्यक्ति जी.एस.डी.पी. क्रमशः ₹ 87,127, ₹ 78,827, ₹ 1,21,382 और ₹ 1,26,121 थी।

1.1.1 सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.)¹

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) एक निश्चित अवधि में राज्य की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। जी.एस.डी.पी. की वृद्धि राज्य की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण संकेतक है, क्योंकि यह एक अवधि में राज्य के आर्थिक विकास के स्तर में परिवर्तन की सीमा को दर्शाता है।

अर्थव्यवस्था के बदलते ढाँचे को समझने के लिए जी.एस.डी.पी. में क्षेत्रीय योगदान में बदलाव भी महत्वपूर्ण हैं। आर्थिक गतिविधि को आम तौर पर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों के अनुरूप होते हैं।

तालिका 1.1: राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में जी.एस.डी.पी. में प्रवृत्ति

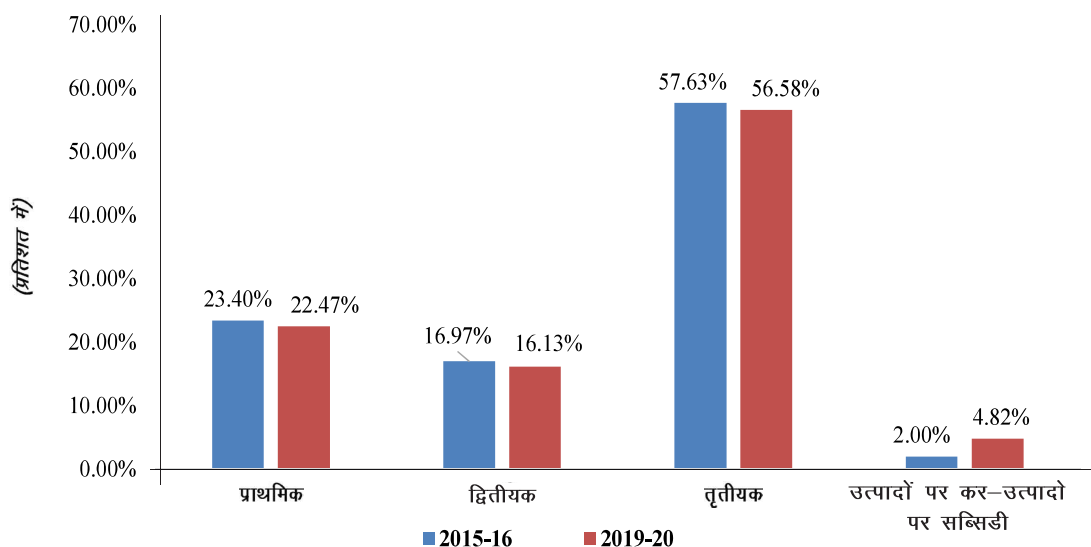
(₹ करोड़ में)

वर्ष	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
भारत सकल घरेलू उत्पाद (2011-12 श्रेणी)	1,37,71,874	1,53,91,669	1,70,98,304	1,89,71,237	2,03,39,849
पिछले वर्ष की तुलना में भारत के सकल घरेलू उत्पाद का वृद्धि दर (प्रतिशत में)	10.46	11.76	11.09	10.95	7.21
राज्य का सकल घरेलू उत्पाद (2011-12 श्रेणी)	3,71,602	4,21,051	4,68,746	5,30,363	6,11,804
पिछले वर्ष की तुलना में जी0एस0डी0पी0 की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	8.35	13.31	11.33	13.15	15.36

(आँकड़े का स्रोत: एम.ओ.एस.पी.आई. प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 31.07.2020)

¹ जी.डी.पी. और जी.एस.डी.पी. क्रमशः देश एवं राज्य के भीतर उत्पादित सभी आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का एक निश्चित अवधि में बाजार मूल्य है तथा देश और राज्य के अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण संकेतक हैं।

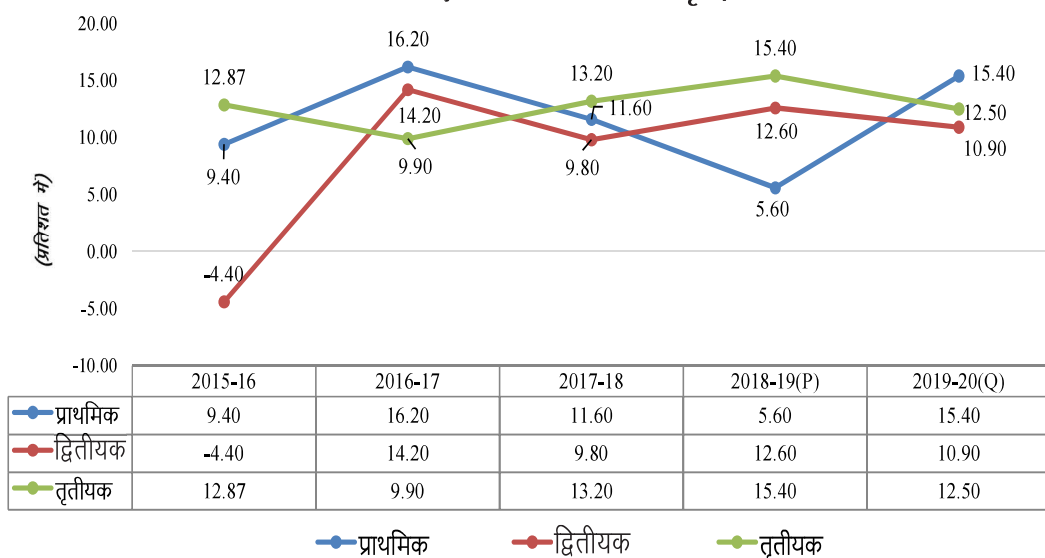
चार्ट 1.1: जी.एस.डी.पी. में क्षेत्रीय योगदान में परिवर्तन (2015-16 और 2019-20)



(आँकड़े का स्रोत: वर्ष 2020-21 का आर्थिक सर्वेक्षण)

राज्य के जी0एस0डी0पी0 में आधे से अधिक का योगदान करने वाले तृतीयक क्षेत्र ने 2015-16 की तुलना में 2019-20 के दौरान अपने सापेक्ष हिस्से में 1.05 प्रतिशत की कमी आई है। 2015-16 की तुलना में 2019-20 के दौरान प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों की सापेक्ष हिस्सेदारी में क्रमशः 0.93 और 0.84 प्रतिशत की कमी आई। चार्ट 1.2 2015-16 से 2019-20 की अवधि के लिए जी0एस0डी0पी0 में क्षेत्रगत वृद्धि को दर्शाता है।

चार्ट 1.2: जी.एस.डी.पी. में क्षेत्रगत वृद्धि



(आँकड़े का स्रोत: वर्ष 2020-21 का आर्थिक सर्वेक्षण)

खनन और उत्खनन, पशुधन, वानिकी और सिल्ली निर्माण में वृद्धि के कारण वर्ष 2019-20 में प्राथमिक क्षेत्र की वृद्धि 2018-19 की तुलना में 5.60 प्रतिशत से बढ़कर 15.40 प्रतिशत हो गई थी। पिछले वर्ष की तुलना में द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों की वृद्धि दर में कमी आई है।

1.2 राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का आधार और दृष्टिकोण

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के अनुसार, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (नि.म.ले.प.) की किसी राज्य के खातों से संबंधित प्रतिवेदन राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत की जानी है, जो उन्हें राज्य विधानमंडल के समक्ष रखने के लिए प्रेरित करेगा। राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एस.एफ.ए.आर.) भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के तहत तैयार और प्रस्तुत की जाती है।

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) राज्य के नियंत्रणाधीन कोषागारों, कार्यालयों एवं विभागों द्वारा प्रदान किये गये वाउचरों, चालानों एवं प्रारम्भिक एवं सहायक लेखों तथा रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरणों से प्रतिवर्ष राज्य के वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे तैयार करता है। इन खातों की स्वतंत्र रूप से महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा लेखापरीक्षा की जाती है और इसे नि.म.ले.प. द्वारा प्रमाणित किया जाता है।

राज्य के वित्त लेखे और विनियोग लेखे इस प्रतिवेदन के मुख्य आँकड़े हैं। अन्य स्रोतों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- राज्य का बजट अनुमानों के साथ-साथ राजकोषीय मानकों और आवंटन प्राथमिकताओं का आकलन करने के लिए, साथ ही साथ इसके कार्यान्वयन की प्रभावशीलता और प्रासंगिक नियमों और निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुपालन का मूल्यांकन करने के लिए;
- कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा किए गए लेखापरीक्षा के परिणाम;
- विभागीय प्राधिकारियों और कोषागारों के पास अन्य आँकड़े (लेखा के साथ-साथ एम.आई.एस.);
- जी.एस.डी.पी. आँकड़े और राज्य से संबंधित अन्य आँकड़े; तथा
- भारत के नि.म.ले.प. की विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा, बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम तथा भारत सरकार की सर्वोत्तम प्रथाओं और दिशानिर्देशों के आलोक में भी यह विश्लेषण किया गया है।

1.3 प्रतिवेदन संरचना

राज्य के वित्त प्रतिवेदन को निम्नलिखित चार अध्यायों में संरचित किया गया है:

अध्याय-I	<p>अवलोकन</p> <p>यह अध्याय प्रतिवेदन और अंतर्निहित आँकड़ों के आधार और दृष्टिकोण का वर्णन करता है, सरकारी लेखों की संरचना, बजटीय प्रक्रियाओं, प्रमुख सूचकांकों के मैक्रो-वित्तीय विश्लेषण और घाटे/अधिशेष सहित राज्य की राजकोषीय स्थिति का एक सिंहावलोकन प्रदान करता है।</p>
अध्याय-II	<p>राज्य के वित्त</p> <p>यह अध्याय राज्य के वित्त का एक व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है, पिछले वर्ष की तुलना में प्रमुख राजकोषीय समुच्चय में महत्वपूर्ण परिवर्तनों, 2015-16 से 2019-20 की अवधि के दौरान समग्र रुझान, राज्य का ऋण प्रोफाइल और प्रमुख लोक लेखा राज्य के वित्त लेखों के आधार पर लोक लेखा का विश्लेषण करता है।</p>

अध्याय-III	बजटीय प्रबंधन यह अध्याय राज्य के विनियोग लेखों पर आधारित है और राज्य सरकार के विनियोग और आवंटन प्राथमिकताओं की समीक्षा करता है और बजटीय प्रबंधन से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों से विचलन पर प्रतिवेदन करता है।
अध्याय-IV	लेखाओं की गुणवत्ता एवं वित्तीय प्रतिवेदन संव्यवहार यह अध्याय राज्य सरकार के विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा प्रदान किए गए लेखों की गुणवत्ता और राज्य सरकार के विभिन्न विभागीय अधिकारियों द्वारा निर्धारित वित्तीय नियमों और विनियमों के गैर-अनुपालन के मुद्दों पर टिप्पणी करता है।

1.4 सरकारी लेखा संरचना और बजटीय प्रक्रियाएं

राज्य सरकार के लेखों को तीन भागों में रखा जाता है:

1. राज्य की समेकित निधि (भारत के संविधान का अनुच्छेद 266(1))

इस कोष में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, राज्य सरकार द्वारा उठाए गए सभी ऋण (बाजार ऋण, बॉण्ड, केंद्र सरकार से ऋण, वित्तीय संस्थानों से ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत कोष को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ, आदि), तरीके शामिल हैं। इसका अर्थ है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए अग्रिम और राज्य सरकार द्वारा ऋणों के पुनर्भुगतान में प्राप्त सभी धन शामिल हैं। इस निधि से कानून के अनुसार और उद्देश्यों के लिए और भारत के संविधान द्वारा प्रदान किए गए तरीके के अलावा किसी भी धन को विनियोजित नहीं किया जा सकता है। व्यय की कुछ श्रेणियां (जैसे, संवैधानिक प्राधिकारियों का वेतन, ऋण चुकौती आदि), राज्य की समेकित निधि (प्रभारित व्यय) पर एक प्रभार का गठन करती है और विधायिका द्वारा मतदान के अधीन नहीं होती है। अन्य सभी व्यय (दत्तमत व्यय) पर विधानमंडल द्वारा मतदान किया जाता है।

2. राज्य की आकस्मिकता निधि (भारत के संविधान का अनुच्छेद 267(2))

यह निधि एक अग्रदाय प्रकृति की है जिसे राज्य विधानमंडल कानून द्वारा स्थापित किया गया है, और राज्य विधानमंडल द्वारा इस तरह के व्यय के प्राधिकरण के लंबित अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए अग्रिमों को सक्षम करने के लिए राज्यपाल के निपटान में रखा जाता है। राज्य की संचित निधि से संबंधित कार्यात्मक प्रमुख शीर्ष पर व्यय को नामे करके निधि की प्रतिपूर्ति की जाती है।

3. राज्य के लोक लेखा (संविधान का अनुच्छेद 266(2))

उपरोक्त के अतिरिक्त, सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त अन्य सभी सार्वजनिक धन, जहाँ सरकार बैंकर या ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है, को लोक लेखे में जमा किया जाता है। लोक खाते में चुकौती योग्य जैसे लघु बचत और भविष्य निधि, जमा (ब्याज सहित और ब्याज रहित), अग्रिम, आरक्षित निधि (ब्याज सहित और ब्याज रहित), प्रेषण और उचंत शीर्ष (दोनों अस्थायी शीर्ष हैं, अंतिम बुकिंग लंबित हैं) शामिल हैं। सरकार के पास उपलब्ध शुद्ध नकद शेष भी लोक लेखा में शामिल है। लोक लेखा विधानमंडल के मत के अधीन नहीं है।

भारत में राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों के समक्ष प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण प्रस्तुत करना एक संवैधानिक आवश्यकता है (अनुच्छेद 202)।

यह 'वार्षिक वित्तीय विवरण' मुख्य बजट दस्तावेज का गठन करता है। इसके अलावा, बजट में से राजस्व लेखे पर व्यय को अलग करना चाहिए।

राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, गैर-कर राजस्व, संघीय करों/शुल्कों का हिस्सा और भारत सरकार से प्राप्त अनुदान शामिल हैं।

राजस्व व्यय में सरकार के वे सभी व्यय शामिल होते हैं जिनके परिणामस्वरूप भौतिक या वित्तीय संपत्ति का निर्माण नहीं होता है। यह सरकारी विभागों और विभिन्न सेवाओं के सामान्य कामकाज, सरकार द्वारा किए गए ऋण पर ब्याज भुगतान, और विभिन्न संस्थानों को दिए गए अनुदान (भले ही कुछ अनुदान संपत्ति के निर्माण के लिए हो) के लिए किए गए खर्चों से संबंधित होते हैं।

पूँजीगत प्राप्तियों में शामिल हैं:

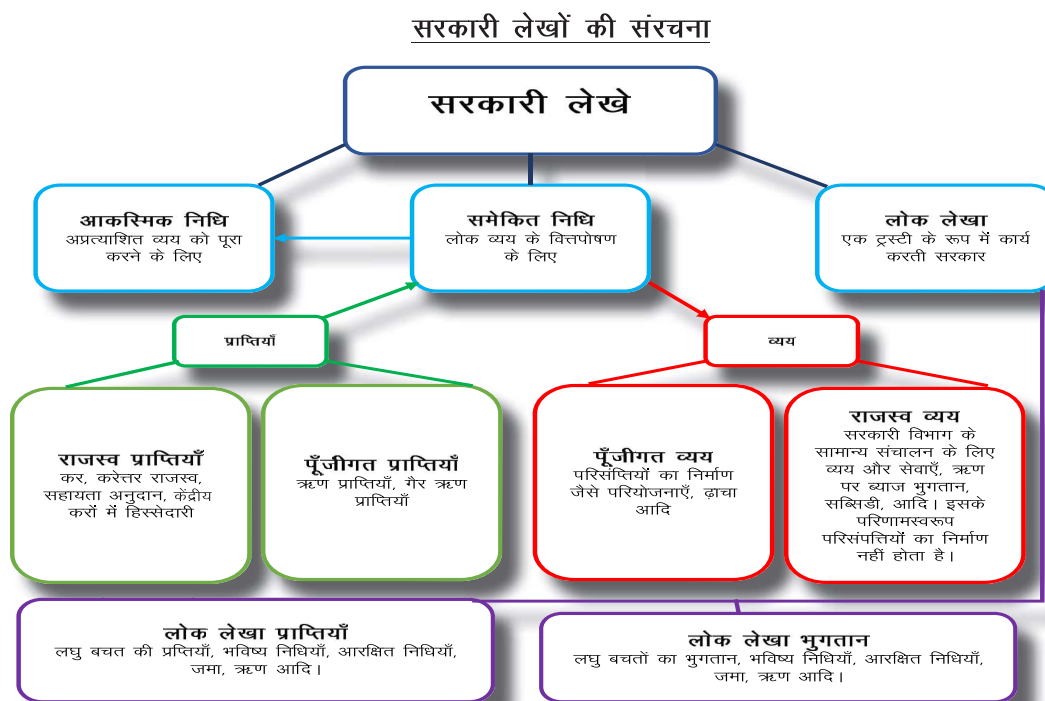
- **ऋण प्राप्तियाँ:** बाजार ऋण, बॉन्ड, वित्तीय संस्थानों से ऋण, अर्थोपाय अग्रिम के तहत शुद्ध लेनदेन, केंद्र सरकार से ऋण और अग्रिम, आदि;
- **गैर-ऋण प्राप्तियाँ:** विनिवेश से प्राप्त आय, ऋणों और अग्रिमों की वसूली;

पूँजीगत व्यय में भूमि, भवन, मशीनरी, उपकरण, शेषों में निवेश, और सरकार द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों और अन्य पार्टियों को ऋण और अग्रिम के अधिग्रहण पर व्यय शामिल होते हैं।

वर्तमान में, हमारे पास सरकार में एक लेखा वर्गीकरण प्रणाली है जो कार्यात्मक और आर्थिक दोनों है।

	लेन-देन का गुण	वर्गीकरण
सी.जी.ए द्वारा मुख्य व लघु शीर्ष सूची में मानकीकृत	कार्य-शिक्षा, स्वास्थ्य, आदि/ विभाग	अनुदान के तहत मुख्य शीर्ष (4-अंकीय)
	उप कार्य	उप मुख्य शीर्ष (2-अंकीय)
	कार्यक्रम	लघु शीर्ष (3-अंकीय)
राज्यों के लिए छोड़ा गया लचीलापन	योजना	उप-शीर्ष (2-अंकीय)
	उप योजना	विस्तृत शीर्ष (2-अंकीय)
	आर्थिक प्रकृति/गतिविधि	विषय शीर्ष-वेतन, लघु कार्य, आदि (2-अंकीय)

कार्यात्मक वर्गीकरण के द्वारा विभाग, कार्य, योजना या कार्यक्रम और व्यय की वस्तु को समझा जाता है। आर्थिक वर्गीकरण इन भुगतानों को राजस्व, पूँजी, ऋण आदि के रूप में व्यवस्थित करने में मदद करता है। आर्थिक वर्गीकरण 4-अंकीय मुख्य शीर्षों के पहले अंक में एम्बेडेड नंबरिंग तर्क द्वारा प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए, 0 और 1 राजस्व प्राप्तियों के लिए है, 2 और 3 राजस्व व्यय आदि के लिए है। आर्थिक वर्गीकरण भी कुछ विषय शीर्षों की एक अंतर्निहित परिभाषा और वितरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए, आम तौर पर "वेतन" विषय शीर्ष राजस्व व्यय है, "निर्माण" विषय शीर्ष पूँजीगत व्यय है। विषय शीर्ष बजट दस्तावेजों में विनियोग की प्राथमिक इकाई है।



बजटीय प्रक्रियाएँ

भारत के संविधान के अनुच्छेद 202 के अनुसार, राज्य के राज्यपाल को राज्य विधानमंडल के समक्ष वर्ष 2019-20 के लिए राज्य की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण **वार्षिक वित्तीय विवरण** के रूप में रखा जाना है। अनुच्छेद 203 के अनुसार, विवरण राज्य विधानमंडल को अनुदान मांगों/विनियोगों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और इनकी स्वीकृति के बाद, विनियोग विधेयक को विधानमंडल द्वारा अनुच्छेद 204 के तहत आवश्यक धन के विनियोग का समेकित निधि से प्रावधान करने के लिए पारित किया जाता है। राज्य बजट मैनुअल, बजट निर्माण प्रक्रिया का विवरण देता है और राज्य सरकार को अपने बजटीय अनुमान तैयार करने और इसकी व्यय गतिविधियों की निगरानी में मार्गदर्शन करता है। बजट की लेखापरीक्षा संवीक्षा और राज्य सरकार की अन्य बजटीय पहलों के कार्यान्वयन का परिणाम इस प्रतिवेदन के **अध्याय III** में विस्तृत है।

1.4.1 संक्षिप्त वित्तीय परिदृश्य

निम्नलिखित तालिका वर्ष 2019-20 के बजट अनुमानों के साथ-साथ वास्तविक वित्तीय परिणामों का विवरण प्रदान करती है।

तालिका 1.2: वित्तीय वर्ष 2019-20 के वास्तविक वित्तीय परिणाम की तुलना बजट अनुमान एवं वर्ष 2018-19 के वास्तविक के साथ

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	घटक	2018-19 (वास्तविक)	2019-20 (बजट अनुमान)	2019-20 (वास्तविक)	बजट अनुमान से वास्तविक की प्रतिशतता	जी.एस.डी.पी. से वास्तविक की प्रतिशतता
1.	कर राजस्व	29,408.14	33,800.00	30,157.98	89.22	4.93
2.	करेतर राजस्व	4,130.56	4,806.47	3,699.60	76.97	0.60
3.	संघीय कर/शुल्कों का अंश	73,603.13	89,121.79	63,406.33	71.15	10.36
4.	भारत सरकार से प्राप्त अनुदान	24,651.62	49,019.38	26,968.62	55.02	4.41
5.	राजस्व प्राप्ति (1+2+3+4)	1,31,793.45	1,76,747.64	1,24,232.53	70.29	20.31

क्र. सं.	घटक	2018-19 (वास्तविक)	2019-20 (बजट अनुमान)	2019-20 (वास्तविक)	बजट अनुमान से वास्तविक की प्रतिशतता	जी.एस.डी.पी. से वास्तविक की प्रतिशतता
6.	ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	1,825.40	416.38	30.40	7.30	0.00
7.	अन्य प्राप्तियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	उधारी एवं अन्य दायित्व	18,668.20	24,420.74	29,145.03	119.35	4.76
9.	पूँजीगत प्राप्तियाँ (6+7+8)	20,493.60	24,837.12	29,175.43	117.47	4.77
10.	कुल प्राप्तियाँ (5+9)	1,52,287.05	2,01,584.76	1,53,407.96	76.10	25.07
11.	राजस्व व्यय	1,24,896.81	1,55,230.65	1,26,016.66	81.18	20.60
12.	ब्याज भुगतान	10,071.14	10,723.47	10,991.42	102.50	1.80
13.	पूँजीगत व्यय	21,058.25	36,592.62	12,303.90	33.62	2.01
14.	ऋणों एवं अग्रिमों	1,470.56	75.50	666.30	882.52	0.11
15.	कुल व्यय (11+13+14)	1,47,425.62	1,91,898.77	1,38,986.86	72.43	22.72
16.	राजस्व आधिक्य (5-11)	6,896.64	21,516.99	(-1,784.13)	(-8.29)	(-0.29)
17.	राजकोषीय घाटा {15-(5+6+7)}	13,806.77	16,101.05	14,723.93	91.45	2.41
18.	प्राथमिक घाटा (17-12)	3,735.63	5,377.58	3,732.51	69.41	0.61

(आँकड़े का स्रोत: वर्ष 2019-20 के लिए राज्य के वित्त लेखे)

(क) संघीय करों से प्राप्त राज्यांश सहित

राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों में 5.74 प्रतिशत की गिरावट आई है। पूँजीगत प्राप्तियों में 42.36 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि पूँजीगत व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में 41.57 प्रतिशत की कमी आई। मुख्य रूप से निगम कर के अंतर्गत प्राप्तियों में ₹ 3,977.90 करोड़ और निगम कर के अलावा अन्य आय पर करों में ₹ 1,911.09 करोड़ की कमी के कारण संघ करों के हिस्से में ₹ 10,196.80 करोड़ की कमी आई है। राज्य सरकार के कुल व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में 5.72 प्रतिशत की गिरावट आई है।

1.4.2 सरकार की परिसंपत्तियाँ और देनदारियों का छायाचित्र

सरकारी लेखे सरकार की वित्तीय देनदारियों और किए गए व्यय से बनाई गई संपत्ति को समाहित करते हैं। देनदारियों में मुख्य रूप से आंतरिक उधार, भारत सरकार से ऋण और अग्रिम, सार्वजनिक खाते और आरक्षित निधि से प्राप्तियाँ शामिल हैं, और संपत्ति में मुख्य रूप से पूँजीगत परिव्यय और राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम और नकद शेष शामिल हैं।

तालिका 1.3 परिसंपत्तियाँ और देनदारियों की संक्षिप्त स्थिति

(₹ करोड़ में)

देयताएँ				परिसंपत्तियाँ					
	2018-19	2019-20	प्रतिशत में वृद्धि		2018-19	2019-20	प्रतिशत में वृद्धि		
समेकित निधि									
अ	आंतरिक ऋण	1,14,359.69	1,36,082.09	18.99	अ	सकल पूँजीगत परिव्यय	2,05,175.42	2,17,479.32	6.00
ब	भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	11,785.37	12,098.16	2.65	ब	ऋण एवं अग्रिम	20,814.33	21,450.23	3.06
आकस्मिकता निधि		350	350			0	0		
लोक लेखा									
अ	लघु बचत, भविष्य निधि, आदि	9,088.69	9,279.09	2.10	अ	अग्रिम	249.96	249.96	0.00

देयताएँ				परिसंपत्तियाँ					
	2018-19	2019-20	प्रतिशत में वृद्धि		2018-19	2019-20	प्रतिशत में वृद्धि		
ब	जमा	33,661.25	35,373.24	5.09	ब	प्रेषण	1,120.36	1,916.87	71.09
स	आरक्षित निधि	4,921.55	6,289.49	27.79	स	उचंचत तथा विविध	4,724.71	10,498.30	122.20
द	उचंचत तथा विविध शेष	0.00	63.85			रोकड़ शेष (उद्विष्ट निधियों का निवेश)	20,837.31	24,912.65	
इ	अंतर्राज्यीय समाशोधन	74.01	74.01						
फ	सरकारी लेखा पर अधिकाई	78,681.53	76,897.40						
	कुल	2,52,922.09	2,76,507.33	9.33		कुल	2,52,922.09	2,76,507.33	9.33

(आँकड़े का स्रोत: वर्ष 2019-20 के लिए राज्य के वित्त लेखे)

1.5 राजकोषीय संतुलन: घाटे और कुल ऋण लक्ष्यों की उपलब्धि

बिहार सरकार ने बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 (बी.एफ.आर.बी.एम) तथा संशोधित अधिनियम, 2016 पारित किया है, जिसका उद्देश्य मध्यम अवधि की रूपरेखा में राजस्व घाटे को समाप्त करने, राजकोषीय घाटे और समग्र/बकाया ऋण को स्वीकार्य स्तर तक कम करके, बेहतर ऋण प्रबंधन की स्थापना और पारदर्शिता में सुधार करके राजकोषीय प्रबंधन में विवेक सुनिश्चित करना है। इस संदर्भ में, अधिनियम घाटे के उपायों और ऋण स्तर के संबंध में राज्य द्वारा पालन किए जाने वाले परिणामात्मक लक्ष्य प्रदान करता है।

तालिका 1.4: बी.एफ.आर.बी.एम अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन

राजकोषीय मापदंड	नियम में निर्धारित राजकोषीय लक्ष्य	उपलब्धि (₹ करोड़ में)				
		2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
राजस्व घाटा (-) / आधिक्य (+) (₹ करोड़ में)	राजस्व आधिक्य	12,507.16	10,819.81	14,823.01	6,896.64	(-) 1,784.13
		✓	✓	✓	✓	✗
राजकोषीय घाटा (-) / आधिक्य (+) (जी0एस0डी0पी0 के प्रतिशतता के रूप में)	3.00 प्रतिशत	(-)12,061.59 (3.25)	(-)16,479.15 (3.91)	(-)14,304.83 (3.05)	(-)13,806.76 (2.60)	(-)14,723.93 (2.41)
		✗	✗	✗	✓	✓
कुल लंबित ऋण का जी0एस0डी0पी0 से अनुपात (प्रतिशत में)	25.73 प्रतिशत	31.37	32.95	33.45	31.85	31.61
		✗	✗	✗	✗	✗

(आँकड़े का स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे तथा बी.एफ.आर.बी.एम. अधिनियम)

तालिका 1.5: 2019-20 के लिए एम.टी.एफ.पी.² में प्रस्तावित अनुमान की तुलना में वास्तविक

(₹ करोड़ में)

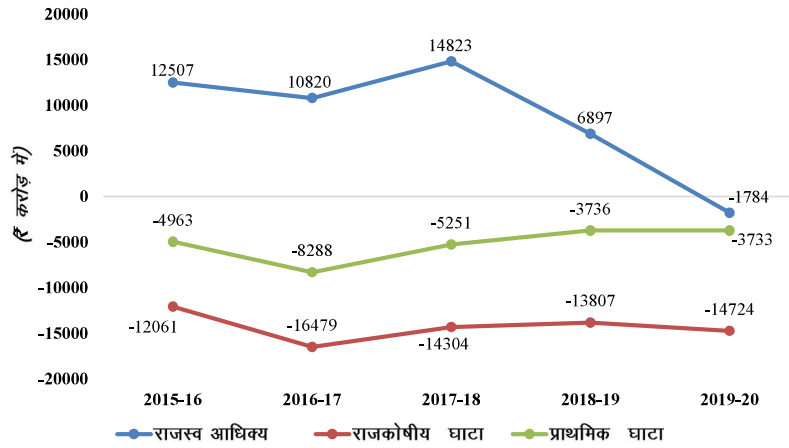
क्र. सं.	राजकोषीय	एम.टी.एफ.पी. में अनुमानित	वास्तविक (2019-20)	अंतर (प्रतिशत में)
1	कर राजस्व	33,800.00	30,157.98	(-)10.78
2	करेत्तर राजस्व	4,806.47	3,699.60	(-)23.03
3	केन्द्रीय कर का अंश/हिस्सा	89,121.79	63,406.33	(-)28.85
4	सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान	49,019.38*	26,968.62	(-)44.98
5	राजस्व प्राप्तियाँ (1+2+3+4)	1,76,747.64	1,24,232.53	(-)29.71
6	राजस्व व्यय	1,55,230.65	1,26,016.66	(-)18.82
7	राजस्व घाटा (-) / आधिक्य (+) (5-6)	21,516.99	(-) 1,784.13	(-)108.29
8	राजकोषीय घाटा (-) / आधिक्य (+)	(-)16,101.05	(-)14,723.93	8.55
9	ऋण-जी0एस0डी0पी0 अनुपात (प्रतिशत)	25.73	31.61	22.85
10	चालू मूल्यों पर जी0एस0डी0पी0 वृद्धि दर (प्रतिशत)	10.56	15.36	45.45

* बिहार सरकार के बजट अनुमान के अनुसार

(आँकड़े का स्रोत: वर्ष 2019-20 के लिए वित्त लेखे एवं बी.एफ.आर.बी.एम. अधिनियम)

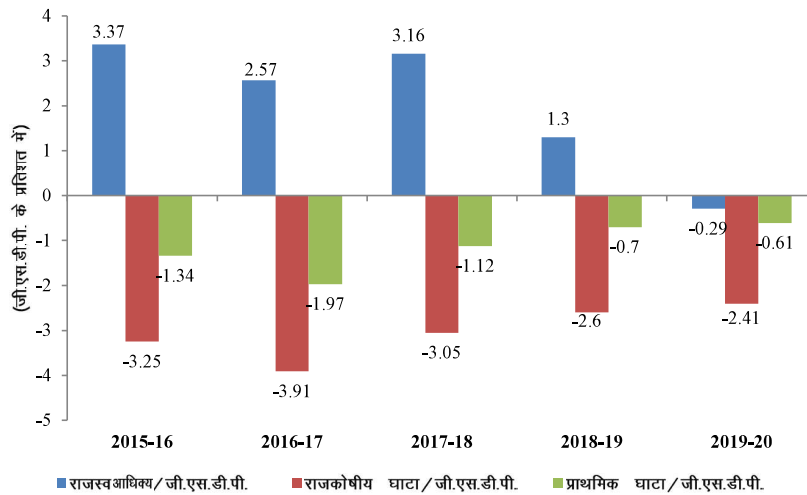
² एम.टी.एफ.पी.- मध्यावधि राजकोषीय नीति

चार्ट 1.3: घाटे के मानकों में प्रवृत्ति



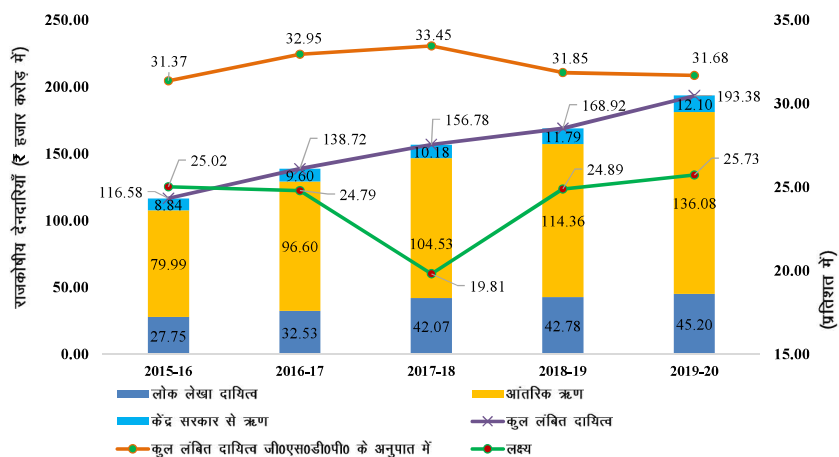
(आँकड़े का स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

चार्ट 1.4: जी.एस.डी.पी. के सापेक्ष आधिक्य/घाटे में प्रवृत्ति



(आँकड़े का स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

चार्ट 1.5: राजकोषीय देनदारियों और जी.एस.डी.पी. की प्रवृत्ति



(आँकड़े का स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

1.6 लेखापरीक्षा में जाँच के बाद घाटा

राज्य के वित्त की बेहतर तस्वीर पेश करने के लिए, राजस्व व्यय को पूँजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत करने की प्रवृत्ति है।

1.6.1 लेखापरीक्षा के बाद – घाटा

राजस्व व्यय का पूँजीगत व्यय के रूप में गलत वर्गीकरण घाटे के आँकड़ों को प्रभावित करता है। इसके अलावा, स्पष्ट देनदारियों को स्थगित करना, समेकित निधि में उपकर/रॉयल्टी जमा नहीं करना, नई पेंशन योजना में कम योगदान, निक्षेप और मोचन निधि आदि भी राजस्व और राजकोषीय घाटे के आँकड़ों को प्रभावित करते हैं। वास्तविक घाटे के आँकड़े निकालने के लिए ऐसी अनियमितताओं का प्रभाव तालिका 1.6 में देखा जा सकता है।

तालिका 1.6: लेखापरीक्षा द्वारा जांच के बाद राजस्व और राजकोषीय घाटा

घटक	राजस्व घाटे पर प्रभाव (न्यूनोक्ति) (₹ करोड़ में)	राजकोषीय घाटे पर प्रभाव (न्यूनोक्ति) (₹ करोड़ में)	कड़िका का संदर्भ
मुख्य शीर्ष –1601 से मुख्य शीर्ष –8121 (एस.डी.आर.एफ.) में धन का हस्तांतरण न करना	553.17	553.17	2.5.2.2
नई पेंशन योजना में कम योगदान	94.19	94.19	2.4.2.3
स्पष्ट देयता का अगले वित्तीय वर्ष के लिए स्थगन	-	123.80	4.2
राजस्व के बजाय पूँजीगत के तहत बजट/बुक किए गए लघु कार्य	50.45	-	3.3.2
ब्याज देनदारियों का निर्वहन न करना	560.33	560.33	4.3
कंपनियों, निगमों या अन्य निकायों में किए गए निवेश/ऋण, जो घाटे में चल रहे हैं या जिनकी कुल संपत्ति पूरी तरह से समाप्त हो गई है। (पूँजीगत व्यय की गुणवत्ता का मुद्दा)	91.80	-	2.4.3.2
कुल	1,349.94	1,331.49	

(स्रोत: वित्त लेखे एवं लेखापरीक्षा विश्लेषण)

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, राज्य का राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा जो ₹ 1,784.13 करोड़ और ₹ 14,723.93 करोड़ था, वास्तव में क्रमशः ₹ 3,134.07 करोड़ और ₹ 16,055.42 करोड़ होगा।